नवदुनियाँ, भोपाल
26 MAY 2015

केन्द्र का हमकदम मध्यप्रदेश

लगातार विजय से जिम्मेदारियां और उन्हें पूरा करने की चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। दिसम्बर 2013 में जब तीसरी बार जीतकर मैं मुख्यमंत्री बना, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। 6 माह के पश्चात नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व से केन्द्र में हमारी सरकार बनी। उनकी सोच, दिशा और गतिशीलता के अनुरूप प्रदेश के विकास और कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना और भी बड़ी चुनौती बन गई। प्रदेश में बिजली, पानी और सड़क के क्षेत्र में पर्याप्त सुधार के बाद हमने मध्यप्रदेश को आधुनिक बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया है।

शिवराज सिंह चौहान

प्रधानमंत्री ने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जो नीतिगत पहल की उन्हें हमने मध्यप्रदेश में पूरी तत्परता से लागू किया। प्रधानमंत्री जन-धन योजना का लक्ष्य पूरा करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। अब प्रदेश में हर परिवार के पास एक बेंक खाता है। अब शासकीय योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर को और आगे बढाया जा रहा है। इसके पहले भी मप्र मनरेगा की मजदूरी और हितग्राही योजनाओं की राशि लाभांवितों के खाते में सीधे जमा करवा रहा था। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजना लागू की है। सामाजिक सुरक्षा देने वाली इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को दिलाने के लिए प्रदेश में अभियान चालाकर कार्य किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को मध्यप्रदेश में पूरी गंभीरता से लिया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता के लिए अलग-अलग रणनीति बनाई गई है। अक्टूबर 2015 से पहले प्रदेश के सभी स्कूलों में शौचालय बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। मेक इन इंडिया की तर्ज पर 'मेक इन मध्यप्रदेश' और 'डिजिटल मध्यप्रदेश' बनाने की पहल भी की गई है।

मेक इन मप्र के अंतर्गत केन्द्र द्वारा रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाए जाने के बाद हमने देश में सबसे पहले रक्षा उत्पादन उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति बनाई है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजायनिंग पॉलिसी भी बनाई है। सेमीकंडक्टर फेब पॉलिसी बनाने वाला भी मध्यप्रदेश पहला राज्य है। भोपाल और जबलपुर के आईटी पार्क में इलेक्ट्रॉनिक मेन्यूफेक्चरिंग यूनिट शुरू की जा रही हैं। देश में पहली बार माइक्रो चिप के निर्माण का गौरव मप्र को प्राप्त होगा।

प्रदेश में उद्योग एवं व्यवसाय को और अधिक सुगम बनाने के लिए हमने ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए हैं। इस संबंध में नियम–कानून और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है। अनावश्यक अनुमतियों को समाप्त किया जा रहा है। उद्योगों के लिए हमने सिंगल डोर पॉलिसी लागू की है। सत्रह केन्द्रीय श्रम कानून में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। वालियंटरी कम्पलाइंस स्कीम लागू की गई है। इसमें इकाइयों को पांच वर्ष में केवल एक बार निरीक्षण की सुविधा दी गई है। सत्रह केंद्रीय श्रम कानून में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इकाइयों को 61 के स्थान पर केवल एक रजिस्टर रखने की सुविधा दी गई है।

प्रदेश में सुशासन की अवधारणा को मूर्तरूप देने में हमने सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग किया है। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन शुरू की गई है। एक बड़ी पहल के रूप में सभी 23 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायत को नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के जरिए ब्राड बेंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जा रही है।

सरकारी दफ्तरों में लोगों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए मैंने प्रभावी कदम उठाए हैं। दस्तावेजों के लिए उन्हें सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा दी गई है। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बीपीएल राशन कार्ड, रोजगार कार्यालय में पंजीयन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, छात्रवृत्ति, बिजली कनेक्शन, निर्माण श्रमिक पंजीयन आदि के कार्यों में शपथ पत्र लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जाति प्रमाण–पत्र ऑनलाइन जारी करने की व्यवस्था भी की है।

सामाजिक क्षेत्र पर हमने बराबर ध्यान दिया है। प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 279 से घटकर 221 तथा शिशु मृत्यु दर 59 से घटकर 54 हो गई है। शिशु मृत्यु दर में यह गिरावट देश में सबसे अधिक है।

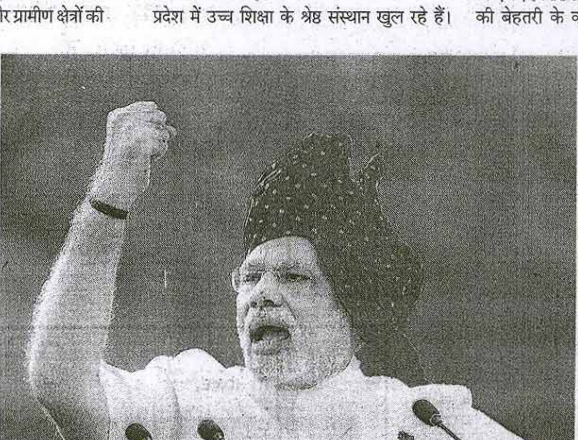

युवाओं को स्किल देने के साथ-साथ हम उन्हें खुद के रोजगार, व्यवसाय शुरू करने में भी मदद कर रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना लागू की गई है। इनोवेटिव आइडियाज के आधार पर उद्योग लगाने के इच्छुक युवा उद्यमियों को पूंजी की व्यवस्था में मदद के लिए 100 करोड़ रुपए का वेंचर केपिटल फंड स्थापित किया गया है।

प्रदेश में उच्च शिक्षा के श्रेष्ठ संस्थान खुल रहे हैं। शत–प्रतिशत बसाहटों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सुविधा सुनिश्चित की गई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के दायरे में अब तक 6 लाख से ज्यादा बच्चों को प्रवेश दिलवाया है। प्रदेश में देश–विदेश की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाएं अब अपने संस्थान स्थापित कर रही हैं। पिछले दिनों इंदौर में नरसी मौंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड साइंस का शिलान्यास किया गया। इसी तरह सिम्बायसिस संस्थान के दो एक्सीलेंस सेन्टर भी इंदौर में स्थापित किए जा रहे हैं। पॉलीटेक्निक, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि में सीट बढ़ाकर युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

उद्योगों के साथ परस्पर सहयोग से प्रशिक्षण के लिए फलेक्सी एमओयू किए जा रहे हैं। शासकीय आईटीआई में नए उद्योगों की मांग के अनुरूप 66 नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। 130 निज़ी नई आईटीआई खुली हैं। गरीबों की बेहतरी के कार्यों को समान रूप से महत्व दिया है।गरीबों को खाद्यान्न सुरक्षा के मामले में मप्र में एक तरह से क्रांति हो गई है। प्रदेश में एक मार्च, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया है। इससे प्रदेश के 42 लाख नए परिवारों के लगभग एक करोड़ 90 लाख सदस्य 1 रुपए प्रति किलो खाद्यान्न, नमक तथा रियायती दर पर शक्कर से लाभान्वित हो रहे हैं। पात्र परिवारों में अन्त्योदल अन्न योजना तथा प्राथमिकता परिवार के रूप में सभी बीपीएल परिवारों के साथ 23 अन्य श्रेणी के गैर बीपीएल परिवारों को भी शामिल किया गया है। अब प्रदेश में लगभग पांच करोड़ की आबादी इस योजना में कवर हो रही है।

युवाओं को स्किल देने के साथ-साथ हम उन्हें खुद के रोजगार, व्यवसाय शुरू करने में भी मदद कर रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना लागू की गई है। इनोवेटिव आइडियाज के आधार पर उद्योग लगाने के इच्छुक युवा उद्यमियों को पूंजी की व्यवस्था में मदद के लिए 100 करोड़ रुपए का वेंचर केपिटल फंड स्थापित किया गया है।

हाल ही में केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय करों के विभाजनीय पूल में से 42 प्रतिशत राशि राज्यों को देने का क्रांतिकारी कदम उठाया है। इससे राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां लागू करने में सुविधा होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'सबका साथ–सबका विकास' का नारा दिया है। मैं मप्र में सभी वर्गों को साथ लेकर और सबके साथ सामान्य व्यवहार करते हुए आधुनिक तथा गतिशील मप्र गढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं। यह कार्य आम जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं है। मैं आह्वान करता हूं कि वे प्रदेश के विकास के इस महायज्ञ में सक्रिय रूप से भागीदार बनें।

(लेखक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)